



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]  
No. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 मार्च, 2003

सं. टीएमपी/15/2002-बीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण खुले और ढके हुए क्षेत्र के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में संशोधन करने हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएमपी/15/2002-बीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (बीपीटी)

आवेदक

आदेश

(मार्च, 2003 के 17वें दिन पारित)

यह मामला खुले और ढके हुए क्षेत्र के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में संशोधन करने हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 बीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- (i) इस समय, 'एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक' के लिए भंडारण क्षेत्र के आबंटन की लाइसेंस फीस दर 'एक वर्ष से कम' की दर से कम है। इस स्थिति के मद्देनजर पत्तन उपयोक्ता क्षेत्र आबंटन की एक वर्ष से अधिक के लिए माँग करते हैं।
- (ii) सामान्यतः पत्तन प्रयोक्ताओं के आबंटन/अपेक्षाएँ आयात/निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इसलिए, केवल एक दर अर्थात् "एक वर्ष से कम" पर विचार करने और "एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक" की प्रविष्टि को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (iii) खुले क्षेत्र और ढके हुए क्षेत्रों को बाद में कस्टम बेरियर के अन्दर और कस्टम बेरियर के बाहर में वर्गीकृत किया जाता है। वास्तव में, ऐसे वर्गीकरण से केवल कुछ मामूली अन्तर आएगा। इसलिए, खुले हुए क्षेत्रों और ढके हुए क्षेत्रों दोनों के लिए अलग-अलग एकसमान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

2.2 इस परिप्रेक्ष्य में, वीपीटी ने दरमान के खण्ड 6 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए अनुमोदन माँगा है :-

**लाइसेंस (भंडारण) फीस प्रभार**

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	दण्डात्मक दर (रुपयों में)
6.1	शैडों के लिए लाइसेंस फीस : ट्रांजिट शैड और भंडारण शैड, मालगोदाम और जी.सी.बी. के पीछे के मालगोदाम सहित सभी ढके हुए क्षेत्र	प्रति 100 वर्ग मीटर	2,975.60 प्रति 15 दिन अथवा उसका भाग।	5,951.20
6.2	खुले क्षेत्र के लिए लाइसेंस फीस : खुला स्टैकिंग क्षेत्र	प्रति 100 वर्ग मीटर	पहले 15 दिनों अथवा उसके हिस्से के लिए 345.00 रुपए और अगले 15 दिनों के लिए अथवा उसके हिस्से के लिए और उससे आगे के लिए 232.90 रुपए।	465.75

3.1 इस प्रस्ताव की प्रति विभिन्न संबंधित प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। विभिन्न प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं से प्राप्त टिप्पणियाँ वीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजी गई थीं।

3.2 इस मामले की संयुक्त सुनवाई 22 जनवरी, 2003 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और पत्तन प्रयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

3.3 अपनाई गई दर के बारे में प्रयोक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के मद्देनजर, वीपीटी प्रयोक्ताओं के साथ बातचीत कर इस मामले की पुनः जाँच करने के लिए तैयार है। तत्पश्चात, वीपीटी ने निम्नलिखित बातों का मुख्य रूप से उल्लेख करते हुए एक पत्र भेजा था :-

- यह प्रस्ताव केवल प्रशुल्क ढाँचे को आसान और युक्तिसंगत बनाने के लिए लाया गया है।
- कस्टम बेरियर के अन्दर अथवा बाहर स्थित भूमियों के अन्तर को दूर करने का प्रस्ताव केवल भूमि के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए है।
- पत्तन के रूप में कोई बदलाव नहीं आया है।

3.4 इस मामले में हुए विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का संकलन संगत पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट ([www.tamp.nic.in](http://www.tamp.nic.in)) पर भी उपलब्ध रहेंगे।

4. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- वीपीटी के प्रस्ताव को वीपीटी के दरमान को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। प्रशुल्क के वर्तमान वर्गीकरण के बारे में पत्तन द्वारा दिए गए कारण सही पाए गए हैं और स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

- (ii) प्रयोक्ताओं ने इस प्रस्ताव पर मुख्य रूप से इस आधार पर आपत्ति की है कि वीपीटी ने प्रशुल्क में पिछले सामान्य संशोधन से बहुत कम समय में दरों में वृद्धि करने की माँग की है। यह स्थिति वर्तमान दरों की उच्चतर दर को वर्तमान वर्गीकरण किए जाने के पश्चात् समान दर के रूप में अपनाने के वीपीटी के रुख का परिणाम है। यह सही है कि इस अपनाए गए तरीके से एक वर्ष से अधिक के लिए आर्बिट्रिट शैडों और कंस्टम बेरियर के बाहर खुले क्षेत्र की दरों में वृद्धि होगी।
- (iii) समझ में यह आता है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य युक्तिकरण है न कि राजस्व बढ़ाना। वीपीटी ने भी इस पहलू को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम परिणामी राजस्व विवक्षा, पत्तन और प्रयोक्ताओं दोनों पर, को बनाए रखने के लिए प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए।
- वीपीटी ने दावा किया है कि प्रयोक्ताओं के लिए भंडारण क्षेत्र की अपेक्षा अस्थायी प्रकृति की है। तथापि एससीआई और एसएआईएल ने बताया है कि बहुत-से बल्क कार्गो प्रयोक्ता वीपीटी का भंडारण क्षेत्र दशकों से प्रयोग कर रहे हैं। निःसंदेह, यदि प्रस्तावित दर को अपनाया जाता है तो ऐसे प्रयोक्ताओं को भारी वृद्धि वहन करनी होगी जोकि इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए अनुमति देना उचित प्रतीत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वर्तमान दरों से कम दर अपनाने से वीपीटी को निश्चित रूप से नुकसान होगा जो वांछनीय नहीं है।
- (iv) जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, यह प्राधिकरण ढाँचे में सरलता और प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने की वीपीटी की पहल का समर्थन करता है। राजस्व निष्पक्ष स्थिति व्यवस्थित कर युक्तिसंगत बनाने का आईएनएसए का सुझाव संगत है। हालांकि, गणना करने के लिए उपलब्ध आँकड़ों के अभाव में राजस्व निष्पक्ष स्थिति के करीब पहुंचने के लिए मारित औसत दर अधिक वैज्ञानिक रहेगी, वर्तमान दरों की सामान्य औसत के रूप में समान दर निर्धारित करना उपयुक्त होगा। यह स्वीकार किया जाता है कि हालांकि इस तरीके से वर्तमान दीर्घकालिक प्रयोक्ताओं के संबंध में कुछ उलझन होगी, परंतु जब इसकी तुलना वर्तमान दरों से अधिक दरों के अपनाए जाने से करेंगे तो यह प्रभाव मामूली हो जाएगा।

5. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी के दरमान का खण्ड

6.1 और 6.2 निम्नवत संशोधित करता है :-

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	दण्डात्मक दर (रुपयों में)
6.1	शैडों के लिए लाइसेंस फीस : ट्रांजिट शैड और भंडारण शैड, मालगोदाम और जी.सी.बी. के पीछे के मालगोदाम सहित सभी ढके हुए क्षेत्र	प्रति 100 वर्ग मीटर	2,231.70 प्रति 15 दिन अथवा उसका भाग।	4,463.40
6.2	खुले क्षेत्र के लिए लाइसेंस फीस : खुला स्टैकिंग क्षेत्र	प्रति 100 वर्ग मीटर	पहले 15 दिनों अथवा उसके हिस्से के लिए 230.70 रुपए और अगले 15 दिनों के लिए अथवा उसके हिस्से के लिए और उससे आगे के लिए 181.10 रुपए।	362.20

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/02-असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th March, 2003

**No. TAMP/15/2002-VPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Visakhapatnam Port Trust about amendment of Licence (Storage) fee for open and covered space as in the Order appended hereto.

**SCHEDULE****Case No. TAMP/15/2002 - VPT****The Visakhapatnam Port Trust**

----

**Applicant****ORDER**

(Passed on this 17th day of March 2003)

This case relates to a proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for revision of Licence (Storage) fees for open and covered space.

- 2.1. The VPT has made the following points in its proposal:
- (i). At present, the rate of licence fee for allotment of storage space for 'a year or more than a year' is less than the rate for 'Less than an year'. In view of this position, port users always demand allotment of area for more than a year.
  - (ii). Normally, allotments/requirements of the port users are of temporary nature for storage of import / export cargoes. Therefore, it is proposed to consider only one rate i.e. "Less than a year" and delete the entry of "a year or more than a year".
  - (iii). The open areas and covered spaces are further classified into area inside the custom barrier and outside the custom barrier. Such classification, in fact, will have only some marginal difference. It is, therefore, proposed to prescribe a uniform rate separately for open spaces and covered spaces.
- 2.2. In this backdrop, the VPT has sought approval to the following modifications in Section 6 of its Scale of rate:

**CHARGES FOR LICENCE (STORAGE) FEE**

Item No.	Description	Unit	Rate (in Rs.)	Penal Rate (in Rs.)
6.1	LICENCE FEE FOR SHEDS: Transit Sheds and Storage Sheds, warehouses and all covered spaces including warehouse behind G.C.B.	Per 100 Sq. Mtrs.	2,975.60 Per fortnight or part thereof.	5,951.20
6.2	LICENCE FEE FOR OPEN SPACE: Open stacking Space	Per 100 Sq. Mtrs.	345.00 for first fortnight or part thereof and Rs. 232.90 for next fortnight or part thereof and onwards.	465.75

- 3.1. A copy of the proposal was forwarded to various concerned users/representative bodies of port users for comments. The comments received from the various users / representative bodies of port users were forwarded to the VPT as feed back information.

3.2. A joint hearing in this case was also held on 22 January 2003 at the VPT premises. At the joint hearing, the VPT and the port users have made their submissions.

3.3. In view of the objections raised by the users about the rates adopted, the VPT agreed to re-examine the matter in consultation with users. Subsequently, the VPT has sent a communication highlighting the following points:

- (i). The proposal is made only to simplify and rationalise the tariff structure.
- (ii). The proposal to do away with the distinction of lands located within or outside customs barrier is only to have transparency in allotment of land.
- (iii). There is no change in the stand of the port.

3.4. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpts of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be available in our website ([www.tamp.nic.in](http://www.tamp.nic.in)).

4. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the VPT is to be seen as an attempt to rationalise its Scale of Rates. The reasons given by the port for doing away with the existing categorization in tariff are found to be genuine and are deserved to be admitted.
- (ii). The users have objected to the proposal mainly on the ground that it seeks upward revision of rates within a short span of time since the last general revision of tariff. This position is as a result of the VPT's stand to adopt the higher of the existing rates as the common rate after doing away the existing categorisation. It is to be admitted that this approach adopted will cause increase in rates for sheds allotted for more than one year and open space outside the customs barrier.
- (iii). It is to be borne in mind that the objective behind this proposal is rationalisation and not revenue enhancement. This aspect has been explicitly admitted by the VPT also. It is needless to point out that care should be taken while rationalising tariff to keep the resultant revenue implication, both on the port and users, at the minimum.

The VPT has claimed that requirement of storage space for users is of temporary nature. The SCI and SAIL have, however, brought out that many bulk cargo users are using the storage area of the VPT for decades. If the proposed rate is adopted, no doubt, such users will face a steep hike which this Authority does not find reasonable to allow for rationalising the tariff. At the same time, adopting the lower of the existing rates will definitely put the VPT in a disadvantageous position which is not desirable.

- (iv). As has been mentioned earlier, this Authority likes to support the initiative of the VPT to rationalise tariff to bring in simplicity in the structure and transparency in the system. The suggestion of the INSA to carry out rationalisation by maintaining a revenue neutral position is relevant. Even though a weighted average rate will be more scientific to reach closer to a revenue neutral position, in the absence of available data for arriving at weights, it may be reasonable to prescribe the common rate as the simple average of the existing rates. It is to be conceded that even this approach will have some implication on the existing long term users but the impact will be moderate when compared with the adoption of higher of the existing rates.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority amends Sections 6.1 and 6.2 of the Scale of Rates of the VPT as follows:

Item No.	Description	Unit	Rate (in Rs.)	Penal Rate (in Rs.)
6.1	LICENCE FEE FOR SHEDS. Transit Sheds and Storage Sheds, warehouses and all covered spaces including warehouse behind G.C.B.	Per 100 Sq. Mtrs.	2231.70 Per fortnight or part thereof.	4463.40
6.2	LICENCE FEE FOR OPEN SPACE: Open stacking Space	Per 100 Sq. Mtrs.	230.70 for first fortnight or part thereof and Rs. 181.10 for next fortnight or part thereof and onwards.	362.20

A. L. BONGIRWAR, Chairman  
[ADVT/III/IV/143/02-Exty.]